THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a) to (d) The construction of a new line from Khurda to Bolangir has already been included in the budget and work on the final location survey and preparation of land acquisition plans is in progress. The survey is being accorded top priority and it is expected to be completed by June' 96.

जम्मू और कश्मीर में हुई हत्याएं

1869. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1995 से अब तक कश्मीर घाटी में बारूदी सुरंगों तथा विस्फोटक उपकरणों की कितनी घटनाएं हुई हैं और इनमें सुरक्षा बलों के कितने जवान मारे गए तथा कितने नागरिक मारे गए अथवा घायल हुये;

(ख) उपरोक्त अवधि में उग्रवादियों द्वारा कितने हमले किये गये तथा इनमें जान-माल की कितनी हानि हुई;

(ग) इस अवधि के दौरान विस्फोटक पदार्थों का पता लग जाने पर उन्हें नष्ट करने की कितनी घटनाएं हुईं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने उग्रवादी मारे गये अथवा पकड़े गये?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.1.1995 से 30.11.1995 तक की अवधि के दौरान, 340 बारूदी सुरंग/आई०ई०डी० विस्फोट हुए जिनमें 79 सुरक्षा बल कार्मिक और 103 सिविलियन मारे गए और 210 सुरक्षा बल कार्मिक और 328 सिविलियन जख्मी हुए।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान आंतकवादी हिंसा की कुल 6227 घटनाऐं हुईं, जिनमें 226 सुरक्षा बल कार्मिक और 110 सिविलियन मारे गए। सम्पति को हुई क्षति में सम्मिलित है:— 125 सरकारी भवन, 130 शैक्षिक संस्थान, लगभग 1800 प्राईवेट भवन और 16 पुल।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सुरक्षा बलों द्वारा कम से कम 130 अवसरों पर विस्फोटक पदार्थों का पता लगाया गया/निष्क्रीय किया गया।

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान 1230 उग्रवादी मारे गए और 2346 गिरफ्तार किए गए।

Target for disinvestment of PSUs shares

1870. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what was the target fixed for the sale of disinvestment shares of the four PSUs;

(b) whether the PSU shares have failed to attract buyers and if so, the reasons therefor; and

(c) what has been the amount realised by each PSU and what steps are proposed to be taken to attract the buyers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVERA): (a) to (c) Govt. undertook disinvestment of PSU shares through auction method in October, 1995. Under this method, no tranche-wise or enterprise-wise targets for sale of shares can be fixed.

27.14 crore shares of 4 PSUs were offered for sale in October, 1995. More than 900 bids for purchase of 7.80 crore shares were received. The PSUs wise details of amount expected to be realised is as per statement enclosed.

Statement

PSU-wise details of amount expected to be realised

Sl. No.	Name of the Company	Amount expected to be realised (Rs. in crores)
1.	Mahanagar Telephone Nigam Ltd.	135.92
2.	Oil & Natural Gas Corporation	5.21

3. Container Corpn. of India	14.12
4. Steel Authority of India Ltd.	13.37
GRAND TOTAL	168.62

Withdrawal of Law/Constitutional provision extended to Jammu & Kashmir

1871. SHRI JAGMOHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any proposal was received from the State Government, during the period 1975 to 1986 and 1987 to 1989 regarding withdrawal of any law or constitutional provision extended to Jammu & Kashmir during the period prior to 1975; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) and (b) The Government of Jammu & Kashmir has stated that the State Government did not propose withdrawal of any law or Constitutional provision extended to the State during the period prior to 1975.

मध्य प्रदेश में शहरी विकास संबंधी 'मेगनेट टाउन' योजना

1872. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन शहरों को 'मेगनेट टाउन' के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) शहरों के ऐसे विकास के लिए तैयार की जाने वाली योजना का शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किन-किन शहरों को शामिल किया गया है; और

(घ) चालू वर्ष में इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु शहर-वार कितनी-कितनी राशि निर्धारित की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के शहरी विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन): (क) मध्य प्रदेश में ग्वालियर सिटी को सम सुविधा सम्पन्न कस्बे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

(ख) ग्वालियर के लिये विकास कोष स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने मार्च 1992 में 1 करोड़ रु० दिये थे। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी मई 1992 में 1 करोड़ रु० दिये थे।

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव में कोई अन्य सिटी/कस्बा शामिल नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने ग्वालियर विकास कोष के लिये चालू वित्त वर्ष हेतु 2 करोड़ रु० का प्रावधान किया है।

Privatisation of CSD

1873. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the steps proposed to privatise the commercial operations of Canteen Stores Department;

(b) whether more transparency has been introduced in the functioning of Canteen Stores Department in 1994-95; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DEPARTMENT OF DEFENCE AND DEPTT. OF DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT) (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c) There is no proposal to privatise the operations of the Canteen Stores Department (CSD).

The functioning of the CSD is periodically reviewed at different levels so as to ensure greater efficiency and transparency.